



politics

आओ, राजनीति करें...

वाला पोस्ट

Website: www.politicswala.com

भोपाल, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 वर्ष-01, अंक-01

एकतरफा राजनीति किनारे कर सुप्रीम कोर्ट का इन्साफ

धार की भोजशाला में नमाज और माँ सरस्वती पूजा दोनों होगी

शुक्र है अदालतें मजहबी नहीं...

फैसला..

23 जनवरी (बसंत पंचमी, शुक्रवार) को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती (वाग्देवी) की पूजा की पूरी छूट दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है।

मध्यप्रदेश के धार जिले की भोजशाला का मामला एक बार फिर गर्म है। ये सामाजिक और मजहबी मुद्दे से ज्यादा अब राजनीतिक लाभ हानि का भी मुद्दा बन गया है। जबकि सारे राजनेता जानते हैं कि ये मामला अदालत तय करेगी। फिर भी आम आदमी और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बीच छवि चमकाने को ऐसी ही शालाएं काम आती हैं।

■ एजेन्सी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धार भोजशाला मामले में बड़ा आदेश दिया है। 23 जनवरी (बसंत पंचमी, शुक्रवार) को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती (वाग्देवी) की पूजा की पूरी छूट दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रशासन को दोनों के लिए अलग-अलग जगह तय करने, विशेष पास व्यवस्था करने और शांति-सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। आदेश के मुताबिक हिंदू समुदाय को हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक निःशुल्क प्रवेश की अनुमति है। उस दिन आगंतुक एक-दो फूल और कुछ चावल के दाने ले जा सकते हैं। इन रियायतों के अतिरिक्त, परिसर अन्य सभी दिनों में पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 1 रुपए होगा। 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

बसंत पंचमी पर दिनभर पूजन होंगे: हिंदू पक्ष

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि बीते कुछ वर्षों से बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। कल बसंत पंचमी है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा, हवन और पारंपरिक अनुष्ठान होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (अरक) के वकील ने अदालत को आश्चर्यचकित किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि पूर्व वर्षों में किया जाता रहा है।

नमाज के बाद परिसर खाली कर देंगे: मस्जिद पक्ष

मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद परिसर खाली कर दिया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया कि नमाज शाम 5 बजे के बाद कराई जाए, ताकि पूजा निर्बाध चल सके। इस पर मस्जिद पक्ष ने स्पष्ट किया कि जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता। अन्य नमाजों के समय में बदलाव संभव है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बसंत पंचमी शुक्रवार को है। ऐसे में प्रशासन को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुशीद, भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज और मध्य प्रदेश राज्य की ओर से महाधिवक्ता को सुना। केएम नटराज ने अरक की ओर से भी पक्ष रखा। इसी प्रकार, आवेदक की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की दलीलें भी सुनी गईं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और महाधिवक्ता ने सुझाव दिया कि जब यह स्पष्ट हो जाए कि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय से कितने लोग आने वाले हैं, तो उसी परिसर के भीतर एक अलग और विशिष्ट स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि निर्धारित समय में नमाज अदा की जा सके। इसी प्रकार, पूर्व प्रथा के अनुसार, बसंत पंचमी के अवसर पर पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करने हेतु हिंदू समुदाय को भी अलग स्थान उपलब्ध कराया जाए।

नमाजियों की संख्या डीएम को बता देंगे: वकील

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुशीद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। खुशीद ने कहा कि 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की अनुमानित संख्या समय रहते और यथासंभव आज ही जिला मजिस्ट्रेट धार को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला प्रशासन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, आगंतुकों के लिए निःशुल्क पास जारी कर सकता है या कोई अन्य निष्पक्ष उपाय अपना सकता है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों।



मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए हम इस पर कोई राय नहीं दे रहे

चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ 2003 में आए अरक के आदेश का मामला है। उस आदेश में अरक ने शुक्रवार को नमाज और मंगलवार व बसंत पंचमी को पूजा की अनुमति दी थी। इस साल बसंत पंचमी शुक्रवार को है। दलील दी गई कि इसके कारण प्रशासन को व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो सकती है। हमने मस्जिद पक्ष, मध्य प्रदेश सरकार और अरक को सुना। याचिकाकर्ता को भी सुना।

संकटमोचक विजयवर्गीय तो शोक भवन में, अब क्या होगा ?

भोजशाला मामले में धार में कल हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। इससे पहले भी ऐसी स्थिति बसंत पंचमी को आई। भोजशाला के मामले में जब जब राज्य की सरकार 'धार' पर सवार हुई, तब तब प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय संकटमोचक बनकर सामने आए हैं। उमा भारती सरकार के समय भी ऐसे ही हालात निर्मित हुए थे। जुम्मा व बसंत पंचमी संग संग आ गए थे। शिवराज सिंह सरकार के समय भी दो मर्तबा ऐसा हुआ।

हर बार कैलाश विजयवर्गीय ने बीच का रास्ता निकाला और दोनों परम्परा को कायम रखा। हालांकि उनके इस कदम से उन्हें बहुसंख्यक समाज की नाराजगी का शिकार भी होना पड़ा लेकिन वे सरकार का 'राजधर्म' कायम करने में कामयाब हुए। इस बार भी विजयवर्गीय ही कसौटी पर थे। इस मर्तबा उनकी जवाबदेही सवैधानिक भी हो गई थी। वे धार जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। लिहाजा इस शुक्रवार को नमाज व पूजन में समन्वय उन्ही के जिम्मे था।

मोहन सरकार भी निश्चित थी कि अनुभवी विजयवर्गीय पूर्व की तरह कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन सरकार की आशाओं पर 'तुषारापात' हो गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शोक भवन में चले गए। उनके परममित्र व पारिवारिक सदस्य के के गोयल की पत्नी का निधन हो गया। नतीजतन विजयवर्गीय ने स्वयं को सार्वजनिक मसलों से दूर कर लिया। इस आशय का एक पत्र भी जारी कर विजयवर्गीय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अब मोहन सरकार पर सबकी नजर है कि वह धार के इस 'धारधार' मसले पर किस पर भरोसा करती हैं।

आठ हजार पुलिसकर्मियों का बल मौजूद

धार में आठ हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस की 'तैयारी पूरी है'। डिप्लॉय का प्लान भी बन चुका है। हम 'सीसीटीवी' से लगातार निगरानी रख रहे हैं। हमने थ्रीडी मैपिंग भी कराई है, जिससे हर 'परिस्थिति का पता चलेगा। बाइक पार्टी और मोबाइल पार्टी द्वारा भी 'नजर रख रहे हैं'। सभी मोहल्लों पर पुलिस की 'नजर है'। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग सिंह ने बताया कि इस बार झेन कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए भीड़ की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अकसिस्टम भीड़ की संख्या, उसकी दिशा और किसी स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत जैसी जानकारीयां रियल टाइम पर उपलब्ध करा रहा है। एसपी मयंक अवस्थी ने कहा कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निगरानी रखी जा रही है।

300 मीटर क्षेत्र नो-फ्लाई जोन

भोजशाला क्षेत्र में 300 मीटर के दायरे में नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में झेन, यूएवी, पैरा ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून सहित किसी भी तरह की उड़ान गतिविधि पर पूरी तरह पाबंदी है। सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर और लावारिस गुमटियां रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन की स्थिति में नगर पालिका सारा सामान जब्त कर सकता है।

- 1034 में परमार शासक राजा भोज ने ज्ञान की साधना और मां सरस्वती की आराधना के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया।
- यह नालंदा, तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था।
- सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभों पर आधारित सभा भवन के शिखर पर देवी-देवताओं की मूर्तियां शोभायमान थीं।

- इस भवन में माघ, बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति, भारकर भट्ट, धनपाल, मानतुगाचार्य जैसे प्रकाण्ड विद्वान अध्ययन व अध्यापन करते थे।
- भवन के उत्तर व दक्षिण की दीवारों पर जालीदार खिड़कियों के बीच देवी-देवताओं की मूर्तियां उकेरी गईं।
- भवन के मध्य में विशाल यज्ञकुंड है। सन 1035 में मां सरस्वती की अप्रतिम सौंदर्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वसंत पंचमी के दिन की गई।

योद्धा

यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी ने एक टी-शर्ट से जीत लिया देश का दिल



टी-शर्ट से बताया जंग का दर्द

■ एजेन्सी, न्यूयॉर्क

यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी ओलेक्सान्द्रा ओलिनिकोवा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के दौरान अपने देश के प्रति प्रेम और समर्थन जताने के लिए एक खास तरीका अपनाया। ओलेक्सान्द्रा पहले दौर के मैच में गत चैंपियन मैडिसन कीज से हार गईं। लेकिन, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सफेद टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था: मुझे यूक्रेनी महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं यहां इस बारे में बात नहीं कर सकती।

खबर के अनुसार, उन्होंने यह तरीका इसलिए चुना क्योंकि ग्रैंड स्लेम के नियम खिलाड़ियों को खेल के मैदान पर राजनीतिक बयान देने से रोकते हैं। उन्होंने टी-शर्ट के जरिए अपनी बात भी कह दी और नियमों का उल्लंघन भी नहीं किया। ओलेक्सान्द्रा के पिता वर्तमान में यूक्रेन की सेना में सैनिक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता उनके सबसे बड़े समर्थक हैं।

उन्होंने बताया कि पिता के सेना में शामिल होने के बाद से उनकी रैंकिंग में 200 से अधिक अंकों का सुधार हुआ है, क्योंकि वह उन्हें गौरवान्वित करना चाहती हैं। उन्होंने साझा किया कि इस टूर्नामेंट की तैयारी उन्होंने यूक्रेन में ही की थी, जहां उन्होंने धमाकों की आवाजें सुनीं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे यूक्रेन के नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा के लिए मदद करें।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों को बताया बिखरा हुआ और कायर समान पुतिन के पास पैसा खत्म तो जंग भी खत्म: जेलेस्की

■ एजेन्सी, दावोस

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेस्की ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन जंग भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने गुरुवार को यह बात स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कही। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका रूसी तेल टैंकर रोक सकता है और तेल जब्त कर सकता है तो यूरोप क्यों नहीं करता। यूरोप के तटों से होकर जाने वाला यही तेल यूक्रेन के खिलाफ जंग को पैसा दे रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पुतिन के पास पैसा नहीं बचेगा तो यूरोप में कोई युद्ध नहीं बचेगा।

जेलेस्की ने कहा कि यही रवैया पहले ईरान के साथ भी देखा गया। वहां लोग आजादी के लिए सड़कों पर उतरे लेकिन आंदोलनों को खून में डुबो दिया गया और दुनिया चुप रही। जेलेस्की बोले- रूसी संपत्तियों से यूक्रेन की रक्षा नहीं की गई उन्होंने यूरोप को याद दिलाया कि रूस की संपत्तियां फ्रीज तो की गईं, लेकिन जब उन्होंने पैसों से यूक्रेन की रक्षा की बात आई तो फेसला रोक दिया गया।

जेलेस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ 'वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल' बनाने को लेकर सिर्फ बैठकें हुईं नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने सीधे पूछा कि क्या यह समय की कमी है या राजनीतिक हिम्मत की। जेलेस्की ने माना कि सुरक्षा गारंटी पर बातें हो रही हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जो वादे किए हैं उसके लिए वे आभारी हैं, लेकिन हर बार बात अटक जाती है। आखिर में कहा जाता है कि ट्रम्प का सहारा चाहिए।

जेलेस्की ने कहा कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। नाटो पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन सिर्फ इस भरोसे पर टिका है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर आगे आएगा, लेकिन अगर अमेरिका नहीं आया तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को आत्मरक्षा करना सीखना होगा। वो ग्रीनलैंड में 14 या 40 सैनिक भेजकर क्या हासिल करना चाहता है? इससे पुतिन को क्या मैसज जाता है, चीन को क्या मैसज जाता है और शायद सबसे जरूरी बात, इससे डेनमार्क को क्या मैसज जाता है?

उन्होंने कहा कि यूक्रेन को ठंडे इलाकों में लड़ने का असली अनुभव है और वह ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है लेकिन वह नाटो का सदस्य नहीं है। ईरान और बेलारूस का जिक्र करते हुए उन्होंने



चेतावनी दी कि जब आजादी के लिए लड़ने वालों की मदद नहीं की जाती तो उसके नतीजे लौटकर आते हैं। बेलारूस में रूस ने मिसाइलों तैनात कर दीं और मिसाइलें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होतीं। जेलेस्की ने कहा कि ग्रीनलैंड के मामले में भी यूरोप वहीं गलती कर रहा है और यह सोचकर बैठा है कि कोई और आकर समस्या सुलझा देगा जबकि इस बीच रूस की युद्ध मशीन लगातार चल रही है।

यूरोप लेकिन बिखरा हुआ: जेलेस्की

जेलेस्की ने यूरोप और अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनियों को रूस को मिसाइल बनाने वाले पुर्जे बेचने से नहीं रोका। यूरोप चुप है अमेरिका लगभग चुप है और पुतिन लगातार मिसाइलें बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बार बार सलाह दी जाती है कि अमेरिका से बातचीत में टॉमहॉक मिसाइलों की बात न करें ताकि माहौल खराब न हो। वहीं यूरोप के अंदर आपसी बहसें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि यूरोप दिखने में सुंदर है लेकिन बिखरा हुआ है और अभी एक सच्ची ताकत नहीं बन पाया है।

ट्रम्प से बातचीत से उम्मीद बढ़ी

ट्रम्प से मुलाकात पर जेलेस्की ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और युद्ध खत्म करने से जुड़े दस्तावेज लगभग तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है लेकिन अब रूस को भी इस आक्रमण को खत्म करने के लिए तैयार होना होगा। अपने भाषण के आखिर में जेलेस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन को अब भाषण नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से ही दुनिया चलती है और अगर आज कदम नहीं उठाया गया तो कल कुछ नहीं बचेगा।

जेलेस्की ने कहा कि गुरुवार को यूक्रेनी टीम की ट्रम्प से मुलाकात हुई। इसके बाद अमेरिकी टीम रूस जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले यूक्रेन के अधिकारी अमेरिकियों से मिलेंगे और फिर अमेरिकी अधिकारी रूसियों से बातचीत करेंगे। जेलेस्की ने मजाक करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि अमेरिकी अधिकारी रूसियों से कब मिलेंगे और हो सकता है उस समय पुतिन सो रहे हों, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस को भी समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि सभी पक्षों को समझौता करने के लिए तैयार होना होगा।

ट्रम्प-जेलेस्की के बीच एक घंटे बात

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज दावा किया कि जेलेस्की से एक घंटे तक बात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि पुतिन के लिए मेरा साफ संदेश है कि यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जेलेस्की के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन मुद्दों पर बात हुई। इससे एक दिन पहले ट्रम्प कह चुके थे कि युद्ध खत्म करने का समझौता अब काफी नजदीक है।

अंतरराष्ट्रीय कानून पैरों तले रौंदा जा रहा दुनिया में दबंग राजनीति की कोशिश

■ एजेन्सी, दावोस

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्विट्जरलैंड के

दावोस में दिए गए अपने भाषण से अंतरराष्ट्रीय हलकों में सनसनी मचा दी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जुबानी हमलों का लगातार सामना कर रहे मैक्रों ने बिगड़ते वर्ल्ड ऑर्डर पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने अपने भाषण में बुलीज जैसे शब्दों का प्रयोग किया और जोर-जबरदस्ती के बजाय सम्मान और नियम-आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात की। मैक्रों ने कहा कि आज दुनिया में दबंग



राजनीति की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि विवाद सामान्य हो चुके हैं।

मैक्रों ने बिना नाम लिए, लेकिन स्पष्ट रूप से अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और इशारा करते हुए कहा कि दुनिया एक नियम-रहित विश्व की ओर बढ़ रही है, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून को पैरों तले कुचला जा रहा है और सिर्फ ताकतवर का कानून चल रहा है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे विश्व भर के नेताओं को आसामनी रंग सनग्लासेज पहने मैक्रों ने संबोधित करते हुए कहा कि देखिए हम किस स्थिति में हैं।

पश्चिमी अफ्रीकी देश में चुनाव की तैयारी, दिसंबर में चुने जाएंगे राष्ट्रपति

■ एजेन्सी, गिनी-बिसाऊ

पश्चिम अफ्रीका के गिनी-बिसाऊ देश ने पिछले साल सैन्य तख्तापलट के बाद अब नई सरकार के गठन के लिए देश में नए चुनावों की तारीख तय कर दी है। जुंटा (सैन्य अधिकारियों का एक समूह जो बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करके देश पर शासन करता है) के नेता जनरल होर्टां डी-ए ने बताया कि राष्ट्रपति और संसद के चुनाव छह दिसंबर को होंगे। जनरल ने एक आदेश जारी कर कहा कि अब देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए माहौल पूरी तरह तैयार है।

पिछले साल नवंबर में सेना ने यहां की सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद पूर्व सेना

प्रमुख इंडा-ए को एक साल के लिए सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली थी। गिनी-बिसाऊ दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। पुर्तगाल से आजादी मिलने के 50 साल बाद भी यहां अक्सर तख्तापलट होता रहता है। पिछले साल अक्टूबर में भी तख्तापलट की एक कोशिश हुई थी।

यह देश लैटिन अमेरिका और यूरोप के बीच इग्स की तरकरी का बड़ा केंद्र माना जाता है। जानकारों का कहना है कि इसी वजह से यहां राजनीतिक संकट बना रहता है। साल 2020 के बाद से पश्चिम अफ्रीका के कई देशों में सेना ने सत्ता संभाली है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो में भी सेना ने सुरक्षा और बेहतर शासन के नाम पर सरकार गिरा दी थी।

सर्वे में दूसरे नंबर पर पहुंची जमात-ए-इस्लामी

बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक पार्टी सरकार बनने के संकेत

■ एजेन्सी, ढाका



बांग्लादेश में अगले महीने होने वाले आम चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक राजनीति से बाहर रही पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी पहली बार सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंचती नजर आ रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हाल ही में हुए दो अलग-अलग सर्वे में जमात देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 300 सीटों संसदीय पर आम चुनाव होंगे।

जमात-ए-इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था और पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। देश की आजादी के बाद 1972 में इस पर बैन लगा दिया गया था। यह बैन 1975 में हटाया गया और 1979 में जियाउर रहमान के शासन में पार्टी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली।

सर्वे में जमात और बीएनपी में मामूली अंतर

अमेरिकी संस्था इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने दिसंबर में कराए गए एक सर्वे में बताया था कि बीएनपी को 33% और जमात को 29% लोगों का समर्थन मिला है। वहीं जनवरी में किए गए एक जॉइंट सर्वे में इटद को 34.7% और जमात को 33.6% समर्थन मिला था। यह सर्वे नरेटिव, प्रोजेक्शन BD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी और जगोरन फाउंडेशन ने मिलकर किया था।

जमात नेता बोले- हम टकराव वाली राजनीति नहीं कर रहे

जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान का कहना है कि उनकी पार्टी अब विरोध और टकराव की राजनीति नहीं बल्कि लोगों के हितों की राजनीति कर रही है। उन्होंने मेडिकल कैंप लगाने, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने और आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को सहायता देने की बात कही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों में पिछली सरकार की नीतियों को लेकर

गुस्सा है, जिसका फायदा जमात को मिला। पार्टी अब 'इस्लाम ही समाधान है' का नारा देकर खुद को एक नैतिक विकल्प के रूप में पेश कर रही है। ढाका में नारियल पानी बेचने वाले मोहम्मद जलाल ने मीडिया से कहा कि लोग अब पुराने दलों से थक चुके हैं और उन्हें जमात एक नया और साफ विकल्प लगती है।

अवामी लीग पर बैन से जमात को फायदा संभव

अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद उनकी पार्टी अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद से नोबेल विजेता मोहम्मद युनुस देश की अंतरिम सरकार चल रहे हैं।

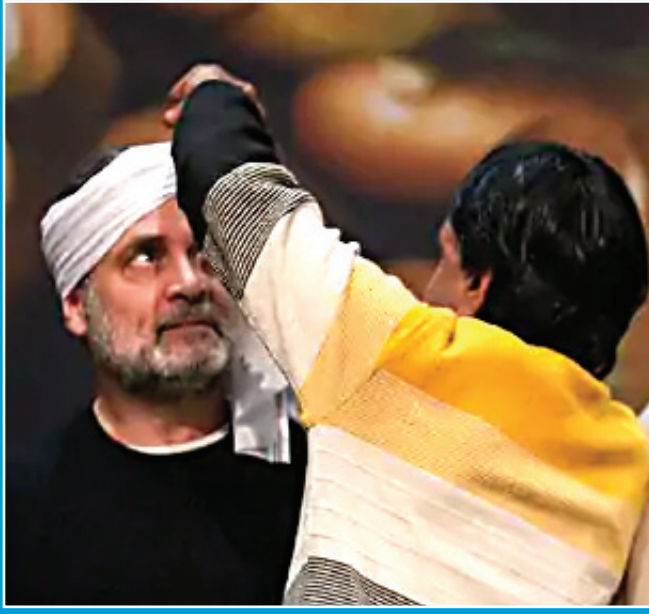
रॉयटर्स के मुताबिक, अवामी लीग पर बैन लगने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में खाली जगह बनी, जिसका फायदा जमात-ए-इस्लामी को मिला। लंबे समय से हाथिए पर रही यह पार्टी अब सत्ता के करीब नजर आ रही है। जमात ने ऐलान किया है कि वह 179 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ बीएनपी की कमान

अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथ में है। खालिदा जिया की हाल ही में मौत हो चुकी है।

बांग्लादेश में भारत के लोकसभा चुनाव जैसी ही चुनावी प्रक्रिया

बांग्लादेश में भी भारत के लोकसभा चुनाव जैसी ही चुनावी प्रक्रिया है। यहां संसद सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के जरिए होता है। यानी जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा, उसी की जीत होगी। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। यहां की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता, जबकि 300 सीटों के लिए हर पांच साल में आम चुनाव होते हैं। भारत की संसद में लोकसभा के अलावा राज्यसभा भी होती है, लेकिन बांग्लादेश की संसद में सिर्फ एक ही सदन है।

कर 'नाटक' ... मजदूरी का लाइट, कैमरा एक्शन



हिंदुस्तान की राजनीति इवेंट राजनीति बन चुकी है। ये तीन तस्वीरें इसकी गवाह हैं। गुरुवार को मनरेगा बचाओ मोर्चा के तहत कांग्रेस ने एक आयोजन किया। अच्छी बात है। इस आयोजन का जिम्मा कर्नाटक कांग्रेस के पास था। ये भी मजदूरों के साथ मजाक ही हैं कि लाखों रुपये से सजे मंच पर कांग्रेस के नेताओं ने मनरेगा मजदूर बनने का नाटक किया। राहुल गांधी ने मंच पर आकर मजदूरों वाला फेंटा बाँधा। फिर नई नवेली कुदाली हाथ में ली और फिर मार्बल के सजे हुए गमलों में पानी डालकर मजदूर की भूमिका निभाई। अब ऐसे कौन मजदूरों के पक्ष में मोर्चा खोलता है। अकेले कांग्रेस ने सभी पार्टियों का यही हाल है, इवेंट के मंच सजाओ नाटक करो छुट्टी पाओ।

■ पॉलीटिक्सवाला



यूपी पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू 16 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान

■ पॉलीटिक्सवाला

यूपी के अमेटी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पदों) के मतपत्र पहुंच चुके हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच, अमेटी जिले में कुल 682 ग्राम पंचायतों के लिए 16,07,921 मतदाता अपने मतदाता कार्ड का प्रयोग करेंगे। यह मतपत्र पुलिस-पीएसी की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखवाए गए हैं।

जिले में 682 ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के लगभग 8,630 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 877 पद और जिला पंचायत सदस्य के 36 पदों पर चुनाव होंगे। चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 16,07,921 है। इन मतदाताओं के लिए विभिन्न पदों के लिए पर्याप्त संख्या में मतपत्र भेजे गए हैं।



जिला पंचायत सदस्य के लिए 20,87,000 मतपत्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 19,63,200 मतपत्र, ग्राम प्रधान के पद के लिए 20,24,500 मतपत्र और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 88,67,000 मतपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इन मतपत्रों

की संख्या मतदाताओं की कुल संख्या से अधिक रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कमी न हो और चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

इन मत पत्रों पर चुनाव चिन्ह छापकर संबंधित ग्राम सभाओं में भेजा जाएगा। मतपत्रों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षा के लिए डबल लॉक सिस्टम अपनाया गया है। यहां पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। पंचायत चुनावों में इन्हीं मत पत्रों से मत पढ़ेंगे। मत पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो चुका है। अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। छह फरवरी तक इसको लेकर शिकायत की जा सकेगी। छह मार्च को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। एडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि मतपत्र छपकर आ चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में पांच लाख मतदाता डुप्लीकेट मिले हैं। इनका सत्यापन कराया जा रहा है।

योगी V/S शंकराचार्य

कुछ लोग सनातन को कमजोर कर रहे: योगी

प्रशासन नोटिस-नोटिस खेल रहा: अविमुक्तेश्वरानंद

■ पॉलीटिक्सवाला

प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और माध मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बांधी घुसाने को लेकर सवाल किए हैं। पूछा है कि क्यों न आपको हमेशा के लिए माध मेले से बैन कर दिया जाए? अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं



वापस ले लेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगिराज ने कहा- प्रशासन ने बुधवार शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चस्पा किया, जिस पर 18 जनवरी की डेट थी। अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार सुबह 8 बजे 3 पेज में दूसरे नोटिस का जवाब मेला ऑफिस भिजवाया। अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से कहा प्रशासन नोटिस-नोटिस खेल रहा है। अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ है, तो मैं बसंत का स्नान कैसे करूंगा? पहले मौनी अमावस्या का स्नान करूंगा, तभी दूसरा स्नान करूंगा।

किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं

सीएम योगी ने अविमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा- किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं। ऐसे तमाम कालनेमि हैं, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। संन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। योगी ने जिस कालनेमि का जिक्र किया, वह रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा था। रावण ने उसको लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को रोकने के लिए भेजा था। बाद में हनुमान ने कालनेमि का वध कर दिया था।

अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सपा ने लगाए पोस्टर

प्रयागराज माध मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोके जाने को लेकर घटित घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा) मैदान में उतर आई है। पार्टी कार्यालय के बाहर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में समाजवादी छात्रसभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर शंकराचार्य का अपमान, नहीं सहंगा हिंदुस्तान लिख कर समर्थन दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। भाजपा को घेरने के लिए अखिलेश यादव कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही फोन पर शंकराचार्य से बात कर उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।

केजरीवाल और अमानतुल्लाह को राहत ईडी के समन की अवहेलना मामले में बरी

■ पॉलीटिक्सवाला

राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

को बड़ी राहत प्रदान की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों में केजरीवाल और ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी द्वारा जारी समनों का पालन न करने के आधार पर केजरीवाल को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

ईडी ने आरोप लगाया था कि जांच के दौरान केजरीवाल को पांच अलग-अलग तारीखों पर समन भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। इसी गैर-अनुपालन के आधार पर ईडी ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान

कहा कि समन का पालन न करना आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता, खासकर जब आरोपी ने अपनी अनुपस्थिति के वैध कारण बताए हों।

ईडी की शिकायतों के अनुसार, दिल्ली की अब रह चुकी आबकारी नीति

से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध थी। एजेंसी ने दावा किया कि नीति में अनियमितताओं से करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई, जिसमें आप नेता शामिल थे। हालांकि, केजरीवाल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां केंद्र

सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं ताकि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा सके।

ईडी ने 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने भी एक अलग भ्रष्टाचार मामले में उन्हें हिरासत में लिया। केजरीवाल को कई हफ्तों तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सितंबर 2024 में उन्हें जमानत मिली।

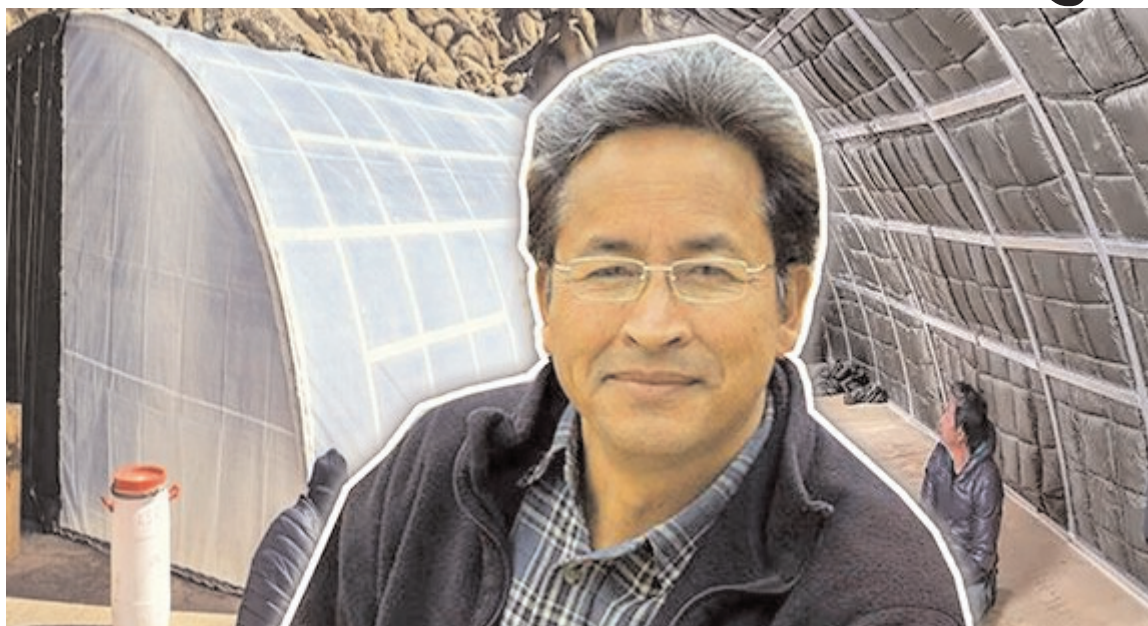


प्रयोगधर्मिता : थमामीटर, चीटियां और वांगचुक !

जेल बैरक में चींटियों का अवलोकन कर रहे हैं वांगचुक, थमामीटर मांगा

■ पॉलीटिक्सवाला

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी और एचआईएल की सह-संस्थापक गीतांजलि जे. आंग्मो ने बुधवार को बताया कि वांगचुक ने जोधपुर जेल में इको-रिस्पॉन्सिव (पर्यावरण के अनुकूल) वास्तुकला पर कुछ प्रयोग करने के लिए थमामीटर मांगा है, ताकि जेल की बैरकों को बेहतर बनाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आंग्मो ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को वांगचुक से मुलाकात की और आखिरकार उन्हें चींटियों और जलवायु परिवर्तन पर वे पुस्तकें सौंप दीं, जिनकी उन्होंने मांग की थी। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कार्यकर्ता और शिक्षक सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कार्यवाई लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए उन प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई थी, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 घायल हुए थे। वह वर्तमान में एकांत कारावास में हैं और जेल में 110 से अधिक दिन बिता चुके हैं। आंग्मो ने कहा, मैंने कल सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उन्हें उनके बड़े भाई द्वारा उपहार में दी गई



चींटियों पर किताब और जलवायु परिवर्तन तथा उसके समाधान पर पुस्तकें दीं। उस पुस्तक का शीर्षक एलेनोर

स्पाइसर राइस और एडुआई फ्लोरिन निगा की एंट्स : वर्कस ऑफ द वर्ल्ड है।

उन्होंने आगे बताया कि वांगचुक ने उनसे जेल प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट से यह पूछने के लिए कहा है कि क्या उन्हें थमामीटर जैसे उपकरण मिल सकते हैं। आंग्मो ने कहा, उन्होंने मुझसे जेल प्रशासन और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से यह पता करने को कहा कि क्या उन्हें थमामीटर जैसे उपकरण मिल सकते हैं, ताकि वे जेल बैरकों को बेहतर बनाने के लिए इको-रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर पर साधारण प्रयोग कर सकें।

उन्होंने मांग की, सोनम वांगचुक को अब रिहा किया जाए ताकि वे शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में अपना राष्ट्र-निर्माण का कार्य जारी रख सकें। इससे पहले पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में आंग्मो ने बताया था कि वांगचुक अपनी जेल बैरक में चींटियों का अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि वे कुछ चींटियों और उनके व्यवहार को देखते हैं, तो वे मुझसे उस पर किताबें लाने को कहते हैं, क्योंकि चींटी समुदाय में बहुत एकजुटता और टीम भावना होती है। शायद वे उसका अध्ययन करना चाहते हैं।

आंग्मो ने वांगचुक की हिरासत को चुनौती देते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को है।

पॉलिटिक्सवाला खबर के आगे... सवाल तो बनता है कलेक्टरों की वसूली पर साहब का 'अनुराग' क्यों ?



■ पॉलिटिक्सवाला, भोपाल

मध्य प्रदेश में खुलेआम रिश्वत चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, खुद सीएस और सीएम को भी ये मालूम है... जिनके हाथ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी हां हम बात कर रहे हैं कलेक्टरों की, कलेक्टर ही क्यों कमिशनर, नगर निगम कमिशनर भी कहां पीछे रहते हैं...

हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कार्रवाई नहीं होती, यदा-कदा इनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है कुछ दिन में ही उन्हें और बड़े जिले, बड़ी जगह पोस्टिंग दे दी जाती है।

मानों भ्रष्टाचार पर सम्मानित किया जा रहा हो, यकीन न हो तो इंदौर नगर निगम कमिशनर का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्हें दूधित पानी मामले में इंदौर से हटाया और कुछ दिन बाद ही मलाईदर पोस्टिंग दे दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर कमिशनर कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया, उन्होंने कहा कि सीएम साहब बोलते हैं कि कोई भी

कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते...

सोचिए प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं और सीएम साहब के हवाले से, यानी सीएम साहब जानते हैं कि कलेक्टर रिश्वत लेते हैं... और इससे भी ऊपर यानी पीएमओ की कलेक्टरों के हर कदम की जानकारी रहती है... यानी पीएमओ भी जानता है कि कलेक्टर बिना लिए दिए काम नहीं करते। फिर किस बात की मजबूरी, कार्रवाई क्यों नहीं करते, कौन सा महूर्त का इंतजार है... अगर वाकई कोई कलेक्टर करप्ट है तो कार्रवाई होनी चाहिए।

बुधवार को सीएस ने कलेक्टर-कमिशनर कॉन्फ्रेंस की दूसरी समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई यह न समझे कि सब कुछ छिपा रहता है। किसके यहां क्या पक रहा है? इसकी पूरी जानकारी रहती है। उन्होंने कहा- एमपी के हर प्रशासनिक मूवमेंट पर पीएमओ नजर रखता है। कलेक्टर चाहें नवाचार करें या किसी तरह की कर्रप्शन जैसी स्थिति में लिप्त हो, पीएमओ तक इसकी जानकारी पहुंचती है। इतना ही नहीं सीएम भी कलेक्टरों की हर एक्टिविटी की जानकारी रखते हैं।

सीएस यही नहीं रुके उन्होंने यह भी कहा कि आप जो

करते हैं, उसे दूसरे राज्यों के लीडर और अफसर भी देखते हैं। वहां से भी फीडबैक आते हैं, जो आपके काम की असलियत उजागर करते हैं। सीएस ने बताया कि कुछ जिलों की शिकायतें उनके और मुख्यमंत्री तक पहुंची हैं, इसलिए समय रहते सुधार कर लें।

आपको बता दें कि कल ही अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह को हटाया गया है। उनके खिलाफ 3 करोड़ के रिश्वत की मांग की शिकायत पीएमओ तक पहुंच गई थी। सीएस के कबूलनामे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मुख्य सचिव के कथित बयान से उत्पन्न गंभीर स्थिति का जिक्र किया है और मध्य प्रदेश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच, जिम्मेदारों को सजा देने और मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेने की मांग की है।

अंत में वही बात... न खाऊंगा, न खाने दूंगा... शायद अब ये भी जुमला ही साबित हो रहा है... क्योंकि अगर सीएस से लेकर पीएम तक ये बात आम हो गई है कि कलेक्टर बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बचा ही क्या।

खेलो एमपी यूथ गेम्स 27 से, मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री मांडविया करेंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

■ पॉलिटिक्सवाला, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ 27 जनवरी को होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विशवास कैलाश सारंग ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएँ सफलतापूर्वक संपन्न हो

चुकी हैं, जबकि जिला एवं संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएँ प्रगति पर हैं और 25 जनवरी 2026 तक पूर्ण हो जाएँगी। इसके पश्चात राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया जाएगा।

मंत्री सारंग ने बताया कि खेलो एमपी यूथ गेम्स में सहभागिता के लिए खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीयन डैशबोर्ड आधारित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया गया है, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी, सरल एवं सुगम बनी है। ब्लॉक स्तर से प्रारंभ हुई इस प्रक्रिया में अब तक एक लाख से अधिक खिलाड़ियों ने

पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि पंजीयन, खेलवार सहभागिता, परिणामों की प्रविष्टि एवं प्रगति की निगरानी रीयल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है।

मंत्री सारंग ने बताया कि चयन प्रक्रिया 313 विकासखंडों से प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 13 से 20 जनवरी 2026 तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ संपन्न की जा चुकी हैं तथा संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएँ 25 जनवरी तक पूर्ण होंगी। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर 21 खेलों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।



भव्य शुभारंभ समारोह, खेलों की थीम पर आधारित आयोजन

मंत्री सारंग ने बताया कि टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित शुभारंभ समारोह को विशुद्ध रूप से खेलों की थीम पर आधारित रखा गया है। समारोह में कैलाश खेर की विशेष प्रस्तुति होगी, वहीं इंडियाज गॉट टैलेंट फेम डांस ग्रुप द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी जाएँगी। इसके अतिरिक्त खेलों के इतिहास पर आधारित नृत्य-नाटिका तथा भव्य आतिशबाजी कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि यह समारोह खेल, ऊर्जा और युवा उत्साह का जीवंत प्रदर्शन होगा।

सिर्फ राजनीति पर केंद्रित देश का पहला दैनिक अखबार



प्रिंट



न्यूज चैनल



प्रिंट + डिजिटल



हम खबरों को देने की जल्दी में नहीं,
तसल्ली से मुकम्मल काम करते हैं...



हमसे जुड़ने के लिए
क्यूआर कोड स्कैन करें

ऑफिस:- भोपाल, इंदौर, दिल्ली, जयपुर

संपर्क- politicswala@gmail.com 7000274400

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज मुकाती द्वारा स्वराज पब्लिकेशन, कोलार रोड, भोपाल से मुद्रित अंकुर कॉम्प्लेक्स फेज-5, 6 नं. स्टॉप भोपाल 462016 (मध्य प्रदेश) से प्रकाशित।

संपादक - पंकज मुकाती। (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा।) आर एन आई नं. एमपीबीआईएल/2019/78225